

प्रेषक,

मनीषा पवार,

समिति,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3,

देहरादून:

दिनांक: 05 जनवरी, 2009

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-1/35/2009 IM(F) दिनांक 20 नवंबर, 2009 तथा पत्र संख्या-1/35/2009 IM(R) दिनांक 20 नवंबर, 2009 जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र सहायित) दिये जाने हेतु कमश धनराशि रु0 15,46,205 (रुपये पन्द्रह लाख छियालीस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि राज्य के 56 छात्रों हेतु तथा 32 छात्रों हेतु धनराशि रु0 8,73,000/- अर्थात् कुल रु0 24,19,205 की की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-77 XVII-03/2008-07(45)/2007 दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा रुपये 2,40,000.00 शासनादेश संख्या-08/XVII-03/2008-07(45)/2007 दिनांक 15 मार्च, 2009 द्वारा रुपये 8,69,295.00 एवं शासनादेश संख्या-239/XVII-03/2008-07(45)/2007 दिनांक 25 मार्च, 2009 द्वारा रुपये 7,00,000.00 एवं शासनादेश संख्या-354/XVII-03/2008-07(45)/2007 दिनांक 02 जून, 2009 द्वारा रुपये

1,30,700.00 तथा शासनादेश संख्या 820/XVII -03/2009-07(45)/2007 दिनांक 16.10.2009 द्वारा धनराशि रू0 5,40,170.00 (पांच लाख चालीस हजार एक सौ सत्तर मात्र) अर्थात् कुल रूपये 24,19,205.00 (रूपये चौबीस लाख उन्नीस हजार दो सौ पांच मात्र) की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। उक्त धनराशि पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुए शासन की भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-15 के 'आयोजनागत' पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से उपरोक्त प्रस्तर-01 में उल्लिखित रू0 24,19,205.00 (रूपये चौबीस लाख उन्नीस हजार दो सौ पांच मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-515(1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 28.07.2009 के क्रम निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (I) उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार एवं शासन की उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।
- (II) आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अथवा नई मदों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।



- (III) उक्त आवंटित धनराशि किसी मद्द पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय हस्तापुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
- (IV) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) के आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (V) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 "आयोजनागत" शब्द स्पष्ट किया जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
- (VI) वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की तिथि से यथाराम्य शासन को अवगत कराया जाए।
- (VII) मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययता/अवचनवद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति कराना सुनिश्चित करें।
- (VIII) अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तापुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (IX) उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
- (X) बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-00-आयोजनागत-800-अन्यव्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाएं-0103- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र सहायित) के मानक मद 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-681(p)/XXVII(3)09-10 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)  
सचिव।

संख्या: <sup>Ind-26</sup> (1)/XVII-03/2009-07(45)/2007, तददिनांक।  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. परिणत कोषाधिकारी, हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण, अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, भारत सरकार, अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
13. बजट, राजकोशीय नियोजन व संसाधन नि०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. आदेश पंजीक।

आज्ञा से,  
(बी०आर० टम्टा)  
अपर सचिव।